दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, शुक्रवार 27 मार्च 2020 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 176

महत्वपूर्ण एवं खास

टोल प्लाजा परिचालन में एमएचए के दिशा-निर्देशों का करें पालन

» एमओआरटीएच की एनएचएआई को सलाह

नईदिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने देश में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन के हालात में एनएचएआई को टोल प्लाजा परिचालन में एमएचए के दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि 24 मार्च को जारी एमएचए के आदेश का खंड 4 कहता है कि 25 मार्च से 21 दिन की अवधि के लिए व्यावसायिक और निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एनएचएआई को एमएचए के आदेशों के क्रम में कदम उठाने की सलाह दी है। इसमें कहा गया कि मौजूदा परिस्थितियों को वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के 19 फरवरी को जारी आदेश की भाषा में रियायत/ अनुबंध समझौते के तहत अप्रत्याशित घटना के तौर पर लिया जा सकता है।

कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 4

जालंधर (आरएनएस)। पंजाब में कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है। ताजा मामला जालंधर में सामने आया है जहां निजातम नगर निवासी एक 70 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इससे लोगों में हड़कंप मच गया है। इसकी पुष्टि नोडल आफिसर डॉटीपी सिंह ने की है। जांच के लिए मौके पर सीपी वेस्ट बरजिंदर सिंह पहुंच गए है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला मरीज अभी लुधियाना के सीएमसी अस्पातल में भर्ती है। सावधानी बरतते हुए पूरे इलाके में सैनिटाइजेशन स्प्रे करवाया जा रहा है। इस मामले को मिलाकर अभी तक महानगर में कोरोना के चार मामले सामने आ चुके है। बता दें, हाल ही में सिविल अस्पताल फिल्लौर में दाखिल 3 रोगियों को कोरोना वायरस होने की पुष्टि हुई थी, जिनकी पहचान गांव विर्क के हरदीप सिंह (25), हरजिंद्र सिंह(50), बलजिंद्र कौर(45) के रूप में बताई गई थी। तीनों करोना वायरस से ग्रस्त नवांशहर के उस व्यक्ति के संपर्क में आए थे जिसकी पिछले दिनों मौत हो चुकी है।

डीजीएफटी ने कोविड-19 से जुड़े आयात-निर्यात हेतु हेल्पडेस्क शुरू किया

नईदिल्ली (आरएनएस)। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत वाणिज्य विभाग के विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने कोविड-19 से जुड़े किसी भी प्रकार के आयात-निर्यात से संबंधित मामलों में सहायता प्रदान करने के लिए हेल्पडेस्क का संचालन शुरू किया है। निर्यातक/आयातक निम्न किसी भी चैनल के माध्यम से सीधे तौर पर अपने मामले से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं।

राहत पैकेज से देश को दिक्कतों से निपटने में मदद मिलेगी:प्रधान

» कोरोना के चलते लॉकडाउन का असर

नईदिल्ली (आरएनएस)। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा आज घोषित राहत पैकेज को अभूतपूर्व बताया और इसे चुनौतीपूर्ण समय में जिम्मेदार शासन प्रणाली का एक उदाहरण कहा। प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद देते हुए, प्रधान ने एक बयान में कहा कि 1.7 लाख करोड़ रूपये के राहत पैकेज से देश को कोविड -19 के प्रकोप से होने वाली दिक्कतों से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने आगे कहा, आज घोषित व्यापक उपाय, ग्रामीण और शहरी गरीबों, किसानों, स्वास्थ्य कर्मचारियों, दूसरी जगहों से आए श्रमिकों, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों पर कोविड-19 के प्रकोप के आर्थिक प्रभाव को कम करेंगे। प्रधान ने कहा कि मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने के निर्णय से लाखों गरीबों को राहत मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि देश में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे।

स्वास्थ्य कर्मी और आशा वर्कर के लिए 50 लाख की होगी बीमा योजना:सीतारमण

» 1 लाख 70 हजार करोड़ के आर्थिक पैकेज » 20 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

नईदिल्ली (आरएनएस)। कोरोना वायरस की वजह से देश में 21 दिनों का लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन की वजह से देश की इकोनॉमी को बड़ा नुकसान होने की आशंका जाहिर की जा रही है। इस बीच, सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी राहत दी है। उन्होंने बताया कि गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को 1.70 लाख करोड़ की मदद की जाएगी। कोरोना संकट के दौरान जो स्वास्थ्य कर्मी डॉक्टर, नर्स तमाम स्वास्थ्य कर्मी इसके साथ ही आशा वर्कर के लिए भी 50 लाख की बीमा योजना का एलान किया है। इससे 20 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा।

वित्त मंत्री ने साथ ही बताया कि कोई गरीब भूखा न रहे, इसके लिए सरकार ने इंतजाम किए हैं। निर्मला सीतारमण ने बताया कि प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत 5 किलो अतिरिक्त गेहूं या चावल अगले तीन महीने तक मिलेगा। इसका फायदा 80 करोड़ लाभार्थी को मिलेगा। इसके अलावा 1 किलो दाल का प्रावधान किया गया है।

अप्रैल के पहले हफ्ते में किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में 2000 रुपये की किश्त डाल दी जाएगी। इसका फायदा 8.69 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिलेगा। मनरेगा के तहत मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाकर 180 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है. इसका फायदा पांच करोड़ परिवारों को फायदा होगा।

उन्होंने बताया कि बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के लिए 1000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। ये अगले तीन महीने के लिए है। इसे दो किस्त में दिया जाएगा. इस वर्ग के लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा। इस पहल का फायदा लगभग 3 करोड़ लोगों को होगा। वहीं करीब 20 करोड़ महिलाओं के खाते में अगले तीन महीने तक 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को तीन महीने तक फ्री सिलिंडर मिलेगा। महिला जनधन खाता धारकों को अगले तीन महीने तक 500 रुपये दिए जाएंगे। इससे 20 करोड़ महिलाओं को फायदा होगा।

यह पैसा भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत दिया जाएगा. अनुराग ठाकुर ने कहा- सरकार कठिन वक्त में मातृ शक्ति के साथ है। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत 7 करोड़ परिवारों को फायदा मिलता है, दीन दयाल राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका योजना के तहत इन्हें जमानत फ्री लोन दोगुना बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जाएगा. इससे 63 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। स्वयं सहायता समूह के लिए भी एलान किया गया. वित्त मंत्री ने कहा- 63 लाख स्वयं सहायता समूह जो इस देश में काम कर रहे हैं, सात करोड़ परिवारों के 35 करोड़ लोग जुड़े हैं. स्वयं सहायता समूह को 10 लाख रुपये मिलता था बिना गारंटी के उसे बढ़ाकर बीस लाख किया जा रहा है । कोरोना वायरस के कहर और लॉकडाउन की वजह से उपजे देश के हालात को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए गुरुवार को व्यापक आर्थिक पैकेज की घोषणा की। लॉकडाउन के बाद गरीबों और मजदूरों को सहायता पहुंचाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.70 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। इससे पहले, वित्त मंत्री ने कहा था कि पैकेज पर काम जारी है और इसकी घोषणा जल्द की जाएगी। आर्थिक पैकेज से इस संकट से पार पाने में मदद मिलेगी। सीतारणम ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने को लेकर 'लॉकडाउन के कारण उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव तथा नौकरियां जाने को लेकर प्रोत्साहन पैकेज की बात कही थी।

» न्याय योजना लागू करने व किसानों एवं छोटे व्यापारियों को राहत देने की मांग

कोरोना पर सोनिया ने मोदी को पत्र लिखकर उपायों का किया समर्थन

नई दिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 21 दिनों के बंद का समर्थन करते हुए बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि न्यूनतम आय गारंटी योजना(न्याय) लागू करके आजीविका के संकट का सामना कर रहे मजदूरों एवं गरीबों के खातों में आर्थिक मदद भेजी जाए और किसानों एवं छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए कदमउठाए जाएं।

प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सोनिया ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए इस संकट से निपटने के लिए पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की महामारी ने लाखों लोगों का जीवन खतरे में डाल दिया है तथा पूरे देश में खासकर समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों की आजीविका एवं रोजमर्रा के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। कोरोना महामारी को रोकने व हराने के संघर्ष में पूरा देश संगठित होकर एक साथ खड़ा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कोराना वायरस से लड़ने के लिए आपकी सरकार द्वारा घोषित 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन का हम समर्थन करते हैं। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि इस महामारी को रोकने के लिए उठाए गए हर कदम में हम सरकार को अपना पूरा सहयोग देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने आग्रह किया कि कोरोना से लड़ रहे चिकित्साकर्मियों के लिए एन-95 मास्क एवं दूसरे सभी स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं।

लॉकडाउन के बीच रोज करेगी 5 करोड़ लोगों के खाने का इंतजाम

नईदिल्ली (आरएनएस)। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया है।

पीएम ने कहा कि इन 21 दिनों में किसी को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने बताया था कि केंद्र और अलग-अलग राज्य सरकारें लोगों के लिए कुछ निर्देश जारी करेंगी। अब केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने खुद ही गरीबों की मदद के लिए आगे आकर उनकी खाने जैसी बुनियादी जरूरत को पूरा करने का फैसला किया है। पार्टी ने ऐलान किया है कि देशभर में मौजूद उसके 1 करोड़ कार्यकर्ता 5 करोड़ गरीबों को खाना मुहैया कराएंगे। इसके लिए हर कार्यकर्ता कम से कम 5 गरीबों के लिए खाने का इंतजाम करेगा।

भाजपा राष्ट्रीय मीडिया के प्रमुख अनिल बलूनी ने बताया कि भाजपा राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह फैसला लिया। उन्होंने सभी नेताओं से अपील की कि लॉकडाउन के दौरान उनके कार्यकर्ता कम से कम 5 गरीबों को खाना दें।

इसके लिए जल्द से जल्द योजना तैयार कर उसे क्रियान्वित करने का आदेश भी दिया जा सकता है। पार्टी की यह योजना ऐसे समय पर आई है, जब कहा जा रहा था कि लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब और दैनिक वेतनभोगी होंगे, जिनके पास रोजाना खाना जुटाने के अलावा कोई चारा नहीं रहता।

बीजेपी के पदाधिकारियों की एक बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गरीब मजदूर और जरूरतमंद लोगों को रोज भोजन मुहैया कराने के लिए महाभोजन अभियान चलाने का निर्णय लिया था। इस अभियान के लिए बीजेपी ने एक करोड़ कार्यकर्ताओं का चयन किया है जिनकी सूची तैयार कर ली गई है।

बीजेपी के पदाधिकारी की बैठक में महाभोजन अभियान चलाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखा गया और इसीलिए लोगों की भीड़ ना हो सोशल डिस्टेंसिंग भी कायम रहे इसके लिए एक कार्यकर्ता की सिर्फ 5 लोगों को भोजन कराने की जिम्मेदारी देने का फैसला किया गया।

राजनाथ ने कोविड-19 से निपटने कार्य-योजना की समीक्षा की

नईदिल्ली (आरएनएस)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए रक्षा मंत्रालय की कार्य-योजना के बारे में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज यहां एक समीक्षा बैठक की।

बैठक के दौरान,रक्षा मंत्री ने कोविड-19 के संक्रमण से प्रभावित देशों में फंसे भारतीय नागरिकों के साथ - साथ विदेशी लोगों को बाहर निकाल लाने और विभिन्न क्वारंटाइन सुविधाकेन्द्रों पर उनकी समुचित देखभाल सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सुरक्षा बलों एवं रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विभागों की सराहना की। उन्होंने सशस्त्र बलों और अन्य विभागों से आग्रह किया कि वे अपनी तैयारियों को लेकर पूरी तरह मुस्तैद रहें और नागरिक प्रशासनको विभिन्न स्तरों पर सभी आवश्यक सहायता प्रदान करें।

बैठक में, अधिकारियों ने राजनाथ सिंह को अब तक उठायेगये विभिन्न उपायों और सहायता के कदमों के बारे में जानकारी दी। भारतीय वायु सेना के विमानों ने कई उड़ानें भरी हैं और चीन, जापान एवं ईरान केसंक्रमण प्रभावित इलाकों से भारतीय नागरिकों को निकाल लिया है।

सशस्त्र बलों के विभिन्न क्वारंटाइन सुविधाकेन्द्रों ने अब तक निकाल लाये गये 1,462 लोगों की देखभाल की है और 389 लोगों को छुट्टी दे दी है। फिलहाल, कुल 1,073 व्यक्तियों को मानेसर, हिंडन, जैसलमेर, जोधपुर और मुंबई के क्वारंटाइन सुविधाकेन्द्रों पर देखभाल की जा रही है। कुल 950 बिस्तरों की क्षमता के साथ अतिरिक्त क्वारंटाइन सुविधा केंद्र स्टैंडबाय पर हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की प्रयोगशालाओं ने 20,000 लीटर सैनेटाइज़र का उत्पादन किया है और दिल्ली पुलिस समेत विभिन्न संगठनों को इसकी आपूर्ति की है। दिल्ली पुलिस को 10,000 लीटर सैनेटाइज़र की आपूर्ति की गयी है। डीआरडीओ ने दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मियों को 10,000 मास्क की आपूर्ति भी की है।

सरकार ने उत्पादकों से हैंड सैनिटाइजर्स का अधिकतम उत्पादन करने कहा

नईदिल्ली (आरएनएस)। नोवेल कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें हर संभव कदम उठा रही हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिएआम जनता,स्वास्थ्यकर्मियों, अस्पतालों आदि के द्वारा हैंड सैनिटाइजर्स का उपयोग किया जा रहा है।सैनिटाइज़र्स की मांग दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तथा मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाए रखने के लिएआबकारी आयुक्तों, गन्ना आयुक्तों,ड्रग कंट्रोलर्स के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के जिला कलेक्टरों सहित राज्य सरकार के अधिकारियों को हैंड सैनिटाइज़र्स के निर्माताओं को इथेनॉल / ईएनए की आपूर्ति में सभी अड़चनों को दूर करने तथा हैंड सैनिटाइज़र्स बनाने के इच्छुक डिस्टिलरी (मद्यशाला) सहित आवेदकों को अनुमति/लाइसेंस देने की सलाह दी गई है। हैंड सैनिटाइज़र्स का थोक में उत्पादन करने में समर्थ डिस्टिलरी/चीनी मिलों को भी हैंड सैनिटाइज़र्स बनाने के लिए प्रेरित किया गया है। अधिकतमउत्पादन करने के लिए इन विनिर्माताओं को तीन पारियों में काम करने के लिए भी कहा गया है।

कोरोना के चलते देशभर के हाईवे टोल फ्री

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आपात सेवाओं का काम आसान करने के लिए देश में अस्थायी तौर पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल नहीं लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने अपनी घोषणा में कहा कि कोविड-19 को देखते हुए आदेश दिया जाता है कि देश के सभी टोल प्लाजा पर टोल लेने का काम बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे आपात सेवाओं के काम में लगे लोगों को जरूरी समय बचाने में मदद मिलेगी। वहीं गडकरी ने अपने ट्वीट में लिखा कि सड़कों के रखरखाव और टोल प्लाजा पर आपातकालीन संसाधनों की उपलब्धता हमेशा की तरह जारी रहेगी। दरअसल देश में 21 दिनों का लॉकडाउन 14 अप्रैल तक चलेगा।

» केंद्र ने राज्यों को दिए दिशानिर्देश

24 घंटे मदद के लिए बनाए कंट्रोल रूम

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्रायलय ने सभी राज्यों से कहा है कि कोरोना वायरस के कारण देश में लगे 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान वो 24 घंटों के लिए कंट्रोल रुम बनाए। जिससे जरूरी वस्तुएं आम जनता तक आसानी से पहुंचाया जा सके और इस बात का ध्यान रखा जाए की जरूरत की चीजों की उपल्बधता बनी रहे।

गृह मंत्रालय ने राज्यों से 24 घंटो के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने को कहा है। मंत्रालय

द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों से कहा गया है कि वो यह सुनिश्चित करें कि उनके राज्य में पूरी तरह से लॉकडाउन के नियमों का पालन हो। साथ ही ये भी कहा है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि परिवहन, वितरण, भंडारण, में कोई समस्या नहीं आए। इसके लिए जिला के स्तर पर भी नोडल ऑफिसर की तैनात करने के लिए कहा गया है। मंत्रालय के दिशा-निर्देश में कहा गया है कि मानक संचालन प्रोटोकॉल(एसओपी)आवश्यक सेवाओं/प्रतिष्ठानों और वस्तुओं के बेहतरी से संचालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसमें अंतर-राज्य की सीमाओं पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, वाहनों के पास या ई-पास आदि से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 को लागू करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन धाराओं के तहत उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और दो साल तक जेल की सजा दी जा सकती है।

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की अवधि बढ़ाई जाएगी

नईदिल्ली (आरएनएस)। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव आनंद कुमार ने एक ट्वीट में कहा है कि लॉकडाउन की अवधि और कार्य बल को दोबारा जुटाने के लिए आवश्यक समय को ध्यान में रखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा की ऐसी सभी परियोजनाओं की अवधि का विस्तार किया जाएगा, जो कार्यान्वयन के अधीन हैं। भारतीय प्रधान मंत्री ने मंगलवार आधी रात से 21 दिन के लिए देश भर में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की थी।